ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
ISSN No.: 2347-2944, RNI:UPBIL04292, REG. No.: 561/2013-2014 Vol.-1, No.-1, PP-231-236,YEAR-2013

भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकार : असफल प्रयोग

❑ डॉ0 आदित्य कुमार गुप्ता

देश की विशालता और विविधता को ध्यान में रखते हुए गठबंधन की राजनीति आज की जरूरत भी बन गयी है। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर किसी एक राजनैतिक दल के उपलब्ध न होने और केन्द्र मे बहुमत जुटाने की विवशता ने चुनावी गठबंधन या चुनाव बाद की साझा सरकार को अपरिहार्य बना दिया है। भले ही गठबंधन की राजनीति अपरिहार्य हो गयी हो लेकिन देश में गठबंधन सरकारों और गठबंधन की राजनीति का इतिहास निराशाजनक रहा है। चुनाव बाद यह प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं होता है कि सरकार किस गठबंधन की बनेगी, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि सामान्यजन के हित यानी राष्ट्रीय सवालों पर मतैक्यता और कार्यान्वयन की स्थिति बनती है या नहीं। यह इसलिये भी कि चारित्रिक रूप से आज सभी गठबंधनों के बीच का अंतर समाप्त हो गया है। सभी सरकार बनाने के लिये जोड़–तोड़ करेंगे, जरूरत पड़ने पर खरीद–फरोख्त भी करेंगे, इसलिये सरकार की क्षमता उसके समर्थक दलों पर ही निर्भर करेगी। पिछले तीन दशकों की 'राजनीतिक संस्कृति' और 'व्यवहार' पर विचार किया जाये तो यह स्पष्ट होता है कि इस काल में सिद्धान्तहीन गठबंधन, विचारधाराहीन दल तथा दिशाहीन नेतृत्व का बोलबाला रहा है। इस तरह की राजनीतिक अपसंस्कृति में भ्रष्टाचार, अपराध, दलबदल, किसी भी कीमत पर कुर्सी हथियाने की अभिलाषा, स्वार्थ लिप्सा, परिवारवाद और खुशामद की प्रचुरता का होना स्वाभाविक है। प्रस्तुत शोध पत्र में भारतीय राजनैतिक परिदृश्य के संदर्भ में गठबंधन सरकारों के असफल प्रयोग को स्पष्ट करने के लिए उनकी सीमाओं एवं असफलताओं के कारणों का विस्तार से विवेचन किया गया है।

गठबंधन सरकारों की कार्य अवधि पर एक दृष्टि डालने से यह स्पष्ट होता है कि ये सभी अल्पकालिक थीं। यह तथ्य गठबंधन सरकारों की स्थिरता पर प्रश्नचिन्ह लगाता है तथा गठबंधन सरकारें किसी राजनीतिक भ्रम व प्रशासनिक अव्यवस्था को बढ़ावा नहीं देंगी, यह संदेह उत्पन्न करता है। 1977 से अब तक केन्द्रीय स्तर पर 11 गठबंधन सरकारें बनीं जबकि मार्च, 1977 और फरवरी, 1997–98 के बीच राज्य विधान सभाओं में 85 अल्पमत वाली सरकारें बनीं। कुछ को सम्माननीय अपवाद के रूप में छोड़ देने पर ज्यादातर सरकारें तदर्थ और अस्थिर प्रकृति की साबित हुयीं। संयुक्त सरकारों का ऐसा निराशाजनक और दुःखद कार्यकलाप इस बात को साबित करता है कि वे कतिपय गंभीर रोगों से ग्रसित रहीं हैं। 1977 से लेकर अब तक के विभिन्न संयुक्त मंत्रिमण्डलों के प्रबंध की चर्चा करते हुये रजनी कोठारी कहते हैं कि वे ''तदर्थ, आकस्मिक और समयोचित'' रहे हैं।

प्रायः गठबंधन सरकारें किसी सर्वसम्मत आदर्शवादिता या अन्य तथ्यों पर आधारित नहीं रही हैं। इनका एक मात्र आधार विरोध की राजनीति रहा है, जो चुनाव पूर्व शर्तों तथा आपसी समझ पर आधारित है।

"Thus Coalition Governments became a game of selfish, opportunist power hungry and unscrupulous politicians who had to look after nothing but their personal interests."

गठबंधन सरकार की सीमाओं का विस्तृत विवेचन निम्न प्रकार से किया जा सकता है–

(1) गठबंधन सरकार के भागीदारों में वैचारिक एकता का अभाव– गठबंधन सरकार के

असिस्टेण्ट प्रोफेसर– राजनीति विज्ञान विभाग, नेशनल पी.जी. कॉलेज, भोगाँव– मैनपुरी (उ0प्र0), भारत

भागीदार दल समान विचारधारा से जुड़े हुये और समानधर्मा हों, तो गठबंधन सरकार एक सुदृढ़ इकाई के रूप में कार्य कर सकती हैं, लेकिन गठबंधन सरकारों के भागीदार दल समानधर्मा नहीं होते हैं, विचारधारा की एकता से जुड़े हुये नहीं होते हैं। गठबंधन सरकारों में वामपंथी, मध्यममार्गी तथा दक्षिणपंथी सभी सम्मिलित होते हैं तथा ये गठबंधन सरकारें विचारधारा और कार्यक्रम की एकता से रहित अवसरवादी गठबंधन के रूप में होती है।

(2) संसदीय सिद्धान्तों के प्रतिकूल आचरण अथवा सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव– संसदीय व्यवस्था में मंत्रिमण्डल से सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के आधार पर कार्यकरण की आशा की जाती है लेकिन अब तक स्थापित कोई भी गठबंधन सरकार अपने कार्यकरण मे सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त का पालन नहीं कर पायी है। मंत्रियों द्वारा न केवल सार्वजनिक रूप से विचार भेद व्यक्त किये गये, वरन् मंत्रियों द्वारा एक–दूसरे की आलोचना भी सामान्य बात थी। इन सरकारों के कार्यकरण को देखकर ऐसा लगता है कि इन सरकारों के भागीदार दलों को सामूहिक उत्तरदायित्व का कोई अभ्यास नहीं है। इन सरकारों के मुख्य पात्रों का अहंभाव भी सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के पालन मे बहुत बड़ी बाधा रहा है।

(3) राजनीतिक दल–बदल को बढ़ावा– अधिकांश गठबंधन सरकारों का जन्म राजनीतिक दल–बदल से हुआ तथा एक बार सरकार बन जाने के बाद भी राजनीतिक दल–बदल की यह स्थिति बनी रही। गठबंधन सरकारों में 'आया राम गया राम' की प्रवृत्ति बनी रही और यह प्रवृत्ति ही इन सरकारों की असफलता तथा अंत का कारण बनी।

(4) नीतियों की अस्पष्टता एवं अनिश्चितता– वर्तमान में गठबंधन सरकारों की नीतियों तथा कार्यक्रमों की अनिश्चितता एंव अस्पष्टता को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। गठबंधन सरकार में शामिल विभिन्न दल हर प्रकार से प्रयास करते हैं कि उन्हें अच्छे से अच्छा विभाग मिल जाये और संसद जिसे देश के लिये नीति निर्माण करना होता है तथा राष्ट्रीय मुद्दे सुलझाने पड़ते हैं, वह विभागीय बंटवारे के बंदर बाँट मुद्दे सुलझाता ही रह जाता है। गठबंधन सरकार किसी की भी हो, जब तक नीतियों में पारदर्शिता नहीं होगी, और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के प्रति राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं होगी, सरकार टिक नहीं सकतीं। नीतियों में जन–सरोकार के अभाव में कोई भी गठबंधन सरकार स्थिर नहीं रह सकती।

(5) भागीदार दलों के बीच मतभेद और तनाव– गठबंधन सरकारों का प्रत्येक भागीदार अपने निहित स्वार्थों की रक्षा में लगा रहता है तथा उनमें से प्रत्येक की दृष्टि आगे आने वाले चुनावों पर लगी रहती है। इस बात के कारण भागीदार दलों में निरन्तर मतभेद और तनाव की स्थिति देखी गयी और ये तनाव ही इन सरकारों के अंत का कारण बने। साथ ही कभी–कभी इन गठबंधन सरकारों में सत्ता संघर्ष और सत्ता से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों के बीच अमर्यादित संघर्ष की स्थिति देखी गयी है।
"The coalition partners were not working as a composite unit on the basis of common programme but were pulling in different directions."

(6) जनादेश विहीनता– 1977 में गठित जनता पार्टी सरकार, 1999 में गठित राजग सरकार तथा 2004 व 2009 में गठित यू॰पी॰ए॰ सरकार को स्पष्ट और संपूर्ण अर्थों में जनादेश प्राप्त था, लेकिन अन्य जो 07 मिली जुली सरकारें गठित हुयीं, उनमें से किसी भी सरकार को जनादेश प्राप्त नहीं रहा है। ये सरकारें जनादेश का नहीं वरन् राजनीतिक परिस्थितियों और राजनीतिक विवशताओं का परिणाम रहीं हैं। इस बात ने इन सरकारों की वैधता और औचित्यपूर्णता को आघात पहुंचाया। लोकतंत्र में 'जनादेश के बिना शासन' एक विडम्बना ही है।

(7) राजनीतिक अस्थायित्व अथवा शासन की अस्थिरता– गठबंधन सरकार के भागीदार दलों के बीच मतभेद और तनाव, राजनीतिक दल–बदल, सरकार मे शामिल कुछ दलों और व्यक्तियों के घोर अनुत्तरदायी आचरण और इन सरकारों के विरूद्ध निरंतर चल रहे षड़यंत्रों के कारण इन सरकारों का औसत जीवन काल केवल कुछ महीने ही होता है।

इन सरकारों का कार्यकाल 13 दिन से लेकर 28 माह रहा है। प्रत्येक गठबंधन सरकार के पद ग्रहण के साथ ही यह प्रश्न खड़ा हो गया कि, 'यह सरकार कब तक बनी रहेगी'। इन गठबंधन सरकारों ने राजनीतिक अस्थायित्व और कुछ परिस्थितियों में घोर राजनीतिक अस्थायित्व को जन्म दिया है। इस राजनीतिक अस्थायित्व ने प्रशासन में दिशाहीनता और प्रशासनिक अनिश्चिय को जन्म दिया।

इतने बड़े देश को चलाने के लिये सरकार बनानी है और वह भी लोकतांत्रिक, ,इसलिये सरकार एक साल में दस बार भी गिर जाये तो 11वीं बार भी उसे बनाना एक मजबूरी है। बार–बार चुनाव करवा कर इस देश मे कोई स्थायित्व आएगा या स्थिर सरकार बनेगी, ऐसी कल्पना करना दिवास्वप्न देखना ही है। क्या सिर्फ चुनाव कराना ही लोकतांत्रिक है ? क्या बार–बार चुनाव देश हित में हैं ? यह लोकतंत्र के लिये घातक है, विकास के मार्ग में अवरोधक है।

(8) व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति पर अधिक बल– राजनीतिक अस्थिरता के दौर में अगर कोई चुना हुआ जन प्रतिनिधि लगातार इस आंशका से ग्रस्त रहे कि उसे किसी भी समय दोबारा चुनाव का सामना करना पड़ सकता है तो उसकी प्राथमिकताये क्या होंगी ? ऐसा व्यक्ति अपना समय, अपनी सोच, अपनी ताकत, अपनी क्रियाशीलता किस दिशा में लगायेगा? वह व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता देगा या देश हित को? वह अपनी कुर्सी बचाये रखने की जोड़–तोड़ में लगेगा या देश–समाज की समस्याओं पर ध्यान देगा? चुने हुए प्रतिनिधियों को लगातार असुरक्षा में रखकर हम उनसे किस भले की उम्मीद करेंगे? जिस तरह एक सामान्य मनुष्य पहले सुरक्षा–बोध चाहता है और उसके बाद उसका कर्तव्य बोध जागता है उसी तरह नेता और मंत्रीगण भी अगर कुछ सुरक्षित महसूस करेंगे तभी वे अपने कर्तव्यों का निर्वाह भी कर सकेंगे।

(9) दुर्बल सरकार– केन्द्र तथा विभिन्न राज्यों में गठबंधन सरकारों का निर्माण हुआ। गठबंधन सरकारों के घटकों मे नीति संबंधी एकता नहीं थी, जिससे गठबंधन में बार–बार मतभेद होते थे और उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता था। गठबंधन के विभिन्न घटकों में कोई तालमेल नहीं था और मंत्रिमण्डल में भी एकता का अभाव था।

प्रो0 रजनी कोठारी के अनुसार "इसके अलावा 1967 के बाद गैर–कांग्रेसी दलों में गठजोड़ होते रहे हैं। अनेक बार ये गठजोड़ बिल्कुल विरोधी और विपरीत दलों में भी हुये हैं। ये गठजोड़ भानुमती के कुनबे जैसे हैं। फलस्वरूप ये गैर–कांग्रेसी संयुक्त सरकारे ज्यादा दिन न चल सकीं और एक के बाद एक गिरती चली गयीं।"

यदि मोरारजी देसाई, चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चन्द्रशेखर, एच॰डी॰ देवगौड़ा, इन्द्रकुमार गुजराल तथा अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्रियों की बात की जाये तो प्रधानमंत्री पद की स्थिति दुर्बल महसूस होती है परन्तु इन सभी में एक समानता है कि ये सभी गठबंधन सरकारों में प्रधानमंत्री थे।

(10) अस्वस्थ विकेन्द्रीकरण– भारत के राजनीतिक अभिजन के एक वर्ग द्वारा अनेक बार यह बात कही जाती रही है कि एक दल की प्रधानता और केन्द्र में एकदलीय सरकारों ने शक्तियों के केन्द्रीकरण को जन्म दिया है तथा गठबंधन सरकारें सत्ता के विकेन्द्रीकरण का पथ प्रशस्त करेंगी और स्वस्थ सहयोगी संघवाद को जन्म देंगी लेकिन व्यवहार में गठबंधन सरकारों ने इन स्थितियों को जन्म नहीं दिया है। व्यवहार में गठबंधन सरकारों ने केन्द्र सरकार की स्थिति को कमजोर किया, केन्द्र–राज्य संबधों और राज्यों के आपसी संबंधों में मतभेद तथा तनाव के नये कारणों को जन्म दिया है और विघटनकारी तत्वों को प्रोत्साहित किया है। ये अस्थिर सरकारें देश को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने में असफल रही हैं। ये सभी सरकारें अपने कार्यकरण में दिशाहीन सरकारें रहीं। जनता को इनमें से प्रत्येक सरकार से भारी निराशा हुयी है। इन सरकारों ने सामान्य जनता के मनोबल को आघात पहुंचाया है।

(11) विरोध की राजनीति– गठबंधन सरकारों के सम्बन्ध में एक परिपाटी आरम्भ से ही रही है कि चाहे जैसी भी सरकार चल रही हो, उसे गिरा दो, कुर्सी से हटा दो, जोड़–तोड़ करके सरकार का

विरोध करो। यह ठीक है कि लोकतंत्र में विपक्ष की अहम भूमिका है। विपक्ष के बगैर सरकार निरंकुश हो जाती है, लेकिन केवल सरकार गिराने के लिये ही विपक्ष का अस्तित्व हो, तो न्याय कहां मिल पाएगा। अगर विपक्ष सरकार गिराने का अधिकार रखता है तो उसे सरकार बनाने का भी अधिकार रखना चाहिये।

(12) सर्वमान्य सैद्धान्तिक राजनीति का अभाव– वर्तमान में गठबंधन अवसरवादिता की आड़ ले कर मजबूरी में हो रहे हैं, जिन्होंने सिद्धान्तों को ताक पर रख दिया है। इनका एक ही लक्ष्य है, केन्द्रीय सत्ता पर आसीन होना, जिसमें क्षेत्रीय शक्तियाँ भी भूमिका निभा रहीं हैं। गठबंधन विचारों – सिद्धान्तों पर आधारित न हो कर राजनीतिक सुविधाओं को ध्यान में रख कर हो रहे हैं, जो देश की व्यवस्था में कभी भी गुणात्मक परिवर्तन नहीं ला सकते, विरोधी विचारधाराओं के गठबंधन स्थायी सरकार कभी नहीं दे पाएंगे, वे केवल लोकतंत्र को संक्रमण काल में पहुँचा सकते हैं।

(13) सुस्पष्ट विचारधारा का अभाव– भारतीय राजनीति में सुस्पष्ट राजनीतिक विचारधाराओं का पूरी तरह से अभाव है। व्यक्तियों पर आधारित राजनीति ने उन्हें समय–समय पर अवसरवादी गठबंधन करके सिद्धान्तहीन राजनीति करने में लगा रखा है। इसलिये राजनीतिक दलों की नीतियों, सिद्धान्तों, आदेशों और कार्यक्रमों में कुछ बातों को छोड़ कर अधिकांश बातों में समानता है। वर्तमान समय में विचारधारा के अभाव में सभी दल किसी न किसी रूप में आर्थिक उदारीकरण की नीति का समर्थन कर रहे हैं, भले ही वे राष्ट्रवादी हों, साम्यवादी हों या समाजवादी हों।

गठबंधन सरकारों की असफलता के कारण– आज देश में राजनीतिक संकट चुनावी तालमेल के अभाव के कारण है। परस्पर विरोधी विचारधाराओं के गठबंधन कभी भी स्थायी नहीं हो सकते; क्योंकि उन गठबंधनों की सर्वोच्च प्राथमिकता सत्ता पर काबिज होना है। उन गठबंधनों की व्यावहारिक राजनीति गायब है। जनता की समस्याएं आकांक्षाएं किसी भी दल के राजनीतिक मुद्दे नहीं हैं। गठबंधनों का तालमेल आज भ्रष्टाचार, अपराध, राष्ट्रद्रोह, धर्म–जाति का पर्याय बन चुका है, जिसमें आदर्शविहीन सिद्धान्त, मूल्यहीन आचरण, भयावह लूट खसोट, जोड़तोड़ की राजनीति चल रही है, जो भविष्य मे गहरे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संकट का पूर्वाभास है।

वर्तमान में समूचा राजनीतिक व्यवहार एक सनकवाद से ग्रस्त है और इसलिये बड़े दलों का टूटना, क्षेत्रीय दलों का उभरना, फिर क्षेत्रीय दलों को टूटना, नये दलों का बनना, फिर नए दलों का किसी क्षेत्रीय दल या बड़े दल के साथ गठबंधित हो जाना, इस गठबंधन की राजनीतिक चालें बदल जाना और कभी–कभी पूरी तरह उलट जाना आदि परिघटनाएं स्थापित या मानक राजनीतिक व्यवहार की समझ से परे रही हैं।

मोहित सेन कहते हैं कि ये संयुक्त मंत्रिमण्डल सरकारें असली संयुक्त मोर्चे होने के बजाय "सुविधा के एक ऐसे गठबंधन मंत्रिमण्डल रहे हैं जिनका अस्तित्व क्षणभंगुर रहा है।"

हमारे देश में संयुक्त मोर्चा की राजनीति जिन कतिपय गंभीर समस्याओं से ग्रसित रही है, उन पर विचार करते हुये इन टिप्पणियों को विस्तारित करने की आवश्यकता है।

इनमें से अधिकांश संयुक्त मंत्रिमण्डल नकारात्मक मोर्चा पर जोड़–तोड़ कर बनने वाले अवसरवादी प्रकृति के रहे हैं। अधिकांश मामलों में संयुक्त मोर्चा के भागीदारों के बीच समानता कम विरोध ही ज्यादा रहे हैं। हम जानते हैं कि जनता पार्टी आपातकाल की ज्यादतियों की उपज थी। चूंकि उसके घटकों के नेता प्राधिकारवादी (अधिनायकवादी) कदमों के सीधे शिकार हुए थे। इसलिये उन्होंने आपस में हाथ मिला लिया था। लेकिन वे कभी भी घटकों के बीच सम्बद्धता विकसित नहीं कर सके। एक ओर सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय लोक दल तथा दूसरी ओर जनसंघ के बीच कोई मिलन स्थल नहीं था। जनसंघ वालों की दोहरी सदस्यता के मसले पर जनता पार्टी सरकार लड़खड़ा गयी। फिर वी0 पी0 सिंह सरकार गैर–कांग्रेसवाद के मोर्चे पर

अस्तित्व में आयी। परिणाम स्वरूप दो परस्पर विरोधी ताकतों वामपंथ और भाजपा ने उसे सहारा दिया। ऐसी सरकार कभी भी स्थिर नहीं हो सकती। चरण सिंह सरकार ओर चन्द्रशेखर सरकार का जन्म इन दोनों नेताओं की जन्म भर की आकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से, घिनौनी दल–बदल की राजनीति के जरिये हुआ। इन दोनों सरकारों के पीछे लेशमात्र का वैचारिक आधार मौजूद नहीं था।

1996–97 की संयुक्त मोर्चा सरकारें चुनाव के बाद पकाई गयी "खिचड़ी" का परिणाम थीं। उनका घोषित और बार–बार दोहराया गया मोर्चा कथित साम्प्रदायिक ताकतों को सत्ता से दूर रखने का था।

राज्यों में संयुक्त मोर्चा सरकारें अधिक अवसरवादी और नकारात्मक रहीं हैं। अस्वस्थ प्रकृति की राज्य स्तर की और क्षेत्रीय दलों के ज्यादा संख्या में पैदा हो जाने से समस्या और बदतर हो जाती है। कुछ राजनैतिक दल निजी लिमिटेड कम्पनियों के रूप में विकसित हुए हैं। वे कुछ नेताओं के जेबी संगठन के रूप में कार्य करते हैं और उनके नेता अपनी सनकों से अंधे बने हुये हैं। वे जिस सरकार में रहते हैं, उसमें भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। इस पर इटली के एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने कहा है, "संयुक्त मोर्चा विवाह का एक ऐसा चरित्र ग्रहण कर लेता है जिसमें प्रेम की अपेक्षा ईर्ष्या अधिक होती है।"

ऐसी परिस्थिति में संयुक्त मंत्रिमण्डल का एक छोटा हिस्सेदार भी बाजीगरी के खेल में लिप्त हो जाता है, सरकार को सुई की नोक पर खड़ा किये रहता है, उसको ऐसे फैसले लेने के लिये मजबूर कर देता है जिनका बचाव अत्यंत कठिन होता है।

ऐसे समय में प्रधानमंत्री या सम्बद्ध मुख्यमंत्री का काम बाहर से देखने वाले अलंघ्य अंतर्विरोधों से छुटकारा पाने में सरकार का ज्यादातर कीमती समय बर्बाद हो जाता है। बाजपेयी कैबिनेट के अकाली सदस्य श्री सुरजीत सिंह बरनाला ने हाल में स्वीकार किया है कि, "संयुक्त मोर्चा सरकार में आपको अत्यंत चौकस और अत्यंत सावधान रहना पड़ता है और वस्तुतः बहुत सारे हितों को देखना पड़ता है और इसके चलते आपका ज्यादातर समय बर्बाद हो जाता है और जिसको आप सचमुच करना चाहते हैं, उसके लिये बहुत थोड़ा समय बच पाता है। ऐसी समस्याओं को सुलझाने में सरकार का ज्यादातर समय बर्बाद हो जाता है और इसके फलस्वरूप प्रशासन को नुकसान पहुंचता है।"

संयुक्त मंत्रिमण्डल के हिस्सेदारों के बीच निरन्तर होने वाली तू–तू–मैं–मैं से और इसके फलस्वरूप सरकार के दयनीय क्रियाकलाप से जनता का मोहभंग हो जाता है और संयुक्त मोर्चा की सरकार की साख बुरी तरह घट जाती है। दल–बदल की राजनीति ऐसी सरकारों की कठिनाइयों को कई गुना बढ़ा देती है। उन्होंने दल–बदल विरोधी अधिनियम को मजाक बना दिया है।

राजनीतिक लाभों और घाटों के रूप मे उसकी व्याख्या की जाती है। संक्षेप में, गठबंधन सरकारें इन राजनीतिक विवशताओं का परिणाम हैं। यदि एक पंक्ति में गठबंधन सरकारों का मूल्यांकन करना हो, तो गठबंधन सरकारों के इस प्रयोग को हम 'असफल प्रयोग' कहने के लिये विवश हैं।

गठबंधन सरकारों की सफलता के लिये जिस समझ, सूझबूझ, राजनीतिक परिपक्वता और संस्कृति की आवश्यकता होती है, हम उस परिपक्वता और राजनीतिक संस्कृति को नहीं अपना पाये हैं। निश्चित रूप से आज चुनाव की राजनीति जिस रास्ते पर जा रही है, उसमे भारत के कल्याण की कोई आशा नहीं, सामाजिक सौहार्द को खतरा है, राष्ट्रीय प्रभुसत्ता को खतरा है, व्यक्ति का जीवन और सम्मान असुरक्षित है।

भवानी सेन गुप्ता की इन पंक्तियों में गहरी सच्चाई है– "मिली–जुली सरकारों के गठन, जीवन तथा कार्यकरण के लिये जिस प्रतिभा और संस्कृति की आवश्यकता होती है, भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में अभी तक वस्तुतः उसका अभाव रहा है। अस्थायी, मिली जुली सरकारों या अल्पमत सरकारों के क्रम ने राज्य के संकट में योगदान किया है, क्योंकि राज्य सरकार के साथ गुंथा हुआ है।"

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. D.C. Gupta : Indian Government and Politics.
2. B. Shivaraman : Bitter Sweet: Gov ernance of India in Transition.
3. Bhawani Sen Gupta : Indian - Prob lems of governance.
4. Chaturvedi, Umar Singh : Indian Politics of the Twentieth Century.
5. Narayan, Iqbal : State Politics in In dia.
6. Sahni, Naresh Chander : Coalition Politics in India.
7. Chaturvedi, Umar Singh : Indian Politics of the Twentieth Century.
8. Grover, V. & Arora, R. : Multi-Party System of Govt of India.
9. Roger Scruton : 'A Dictionary of Po litical Thought'
10. Frontline : "Another reprieve" 9th Sept. 1994
11. शर्मा, राधेश्याम (अनु0) : भारत में जनतन्त्र के नवीन आदर्श।
12. कश्यप, सुभाष : दल–बदल और राज्यों की राजनीति।
13. कश्यप, सुभाष : भारतीय राजनीति व राजनीतिक दल।
14. कोठारी, रजनी : भारत में राजनीति
15. शर्मा, पी0एन0 : महानिर्वाचन और राष्ट्रीय राजनीति।
16. वर्मा, डा0 विश्वनाथ प्रसाद : निर्वाचन और राजनीति।
17. सिंह, डा0 वीरकेश्वर प्रसाद :शासन एवं राजनीति।
18. नारंग, ए0 एस0 : भारतीय शासन एवं राजनीति।
19. कौल, महेश्वर नाथ, शकधर, श्यामलाल : संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार।
20. गुप्ता, मोहिनी गुप्त, विश्वप्रकाश : भारतीय राजनीति – विकास और विश्लेषण।
21. सिंह, विजेन्द्र पाल : हमारे विधायक
22. श्रीवास्तव, शंकर दयाल : भारतीय लोकतंत्रः समस्यायें और संभावनायें।
23. प्रतियागिता दर्पण : 'गठबंधन की राजनीति : समस्यायें और संभावनायें', अग0 1999; पृ0 73.

*****